



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 14 जुलाई, 2025

आषाढ़ 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-3

संख्या 945/38-3-2025-38-3099(99)/11/2022

लखनऊ, 14 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-51

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारियों की सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2025

भाग-एक सामान्य

1-(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2025" कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा एक राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

सेवा की
प्रास्थिति

परिभाषाएं

3—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य जिला विकास अधिकारी से है;

(ग) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) “आयोग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ङ) “आयुक्त” का तात्पर्य आयुक्त, ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश से है;

(च) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(छ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) “नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों” का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा से है;

(ट) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) “ग्राम विकास अधिकारी” का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से और अग्रतर इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति से है;

(ड) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी:—

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		कुल पद
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	ग्राम विकास अधिकारी	8297	—	8297

परन्तु यह कि—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

भाग—तीन— भर्ती

5—आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

भर्ती का स्रोत

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय—समय पर यथासंशोधित “अधिनियम” और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के अनुसार भी तथा भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

आरक्षण

भाग—चार— अर्हताएं

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी,

राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु अग्रतर यह कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा भी की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—(1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

शैक्षणिक
अर्हताएं

(2) एन0आई0ई0एल0आई0टी0 (पूर्ववर्ती डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी) द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण—पत्र।

अधिमानी अर्हताएं	9—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
आयु	10—सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
चरित्र	11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान स्वयं कर लेंगे। टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहली से एक पत्नी जीवित हो: परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।
शारीरिक स्वस्थता	13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—दो भाग—तीन के अध्याय—तीन में अन्तर्विष्ट फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।
	भाग—पाँच—भर्ती हेतु प्रक्रिया
रिक्तियों का अवधारण	14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे आयुक्त को सूचित करेगा। आयुक्त नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचनाओं को संकलित करेगा और सीधी भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेजेगा।
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	15—सेवा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिये सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जाएगी। आयोग चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयुक्त को अग्रसारित करेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए नाम भेजेगा।

भाग-छ:- नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

16-आयोग से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् आयुक्त द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा तथा नियुक्ति हेतु संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को भेजा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समस्त सेवा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

नियुक्ति

17-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परीक्षा पर रखा जाएगा।

परीक्षा

(2) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हों, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

18-उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षावधि अथवा बढ़ाई गई परीक्षावधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि,-

स्थायीकरण

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लिया हो;

(ख) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जाएगा।

19-सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक की ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

ज्येष्ठता

भाग-सात-वेतन इत्यादि

20-(1) सेवा में पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान और भत्ते ऐसे होंगे जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

वेतनमान

(2) इस नियमावली के प्रारंभ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-

पद का नाम	वेतनमान
ग्राम विकास अधिकारी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-3, 21700-69100

21-(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परीक्षा अवधि में वेतन

परन्तु यह कि, यदि संतोष न प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा के दौरान वेतन इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसा व्यक्ति का, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा के दौरान वेतन के सम्बन्ध में सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा जो सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू होते हैं।

भाग—आठ— अन्य उपबंध

पक्ष समर्थन

22—किसी पद या सेवा के लिये लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य मामलों का विनियमन

23—ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्टतः रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे, जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

24—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ, वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उस मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

निरसन और व्यावृत्ति

25—उत्तर प्रदेश ग्राम विकास (ग्राम सेवक) सेवा नियमावली, 1980 को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
हिमांशु कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 945/XXXVIII-3-2025-38-3099(99)/11/2022, dated July 14, 2025:

No. 945/XXXVIII-3-2025-38-3099(99)/11/2022

Dated Lucknow, July 14, 2025

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of services of persons appointed to the Uttar Pradesh Village Development Officers Service:—

THE UTTAR PRADESH VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER SERVICE RULES, 2025

PART- I GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Village Development Officer Service Rules, 2025.

(2) They shall come into force at once.

2. The Uttar Pradesh Village Development Officer Service is a State Subordinate Non-Gazetted Service comprising Group 'C' post. Status of Service

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:— Definitions

(a) '**Act**' means The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) '**Appointing authority**' means the District Development Officer;

(c) '**Citizen of India**' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(d) '**Commission**' means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;

(e) '**Commissioner**' means the Commissioner, Rural Development, Uttar Pradesh;

(f) '**Government**' means the Government of Uttar Pradesh;

(g) '**Governor**' means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) '**Member of service**' means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(i) '**Other backward classes of citizen**' means the backward classes of citizen specified in Schedule-I of the Act, as amended from time to time;

(j) '**Service**' means Uttar Pradesh Village Development Officer Service;

(k) '**Substantive appointment**' means an appointment not being an *ad-hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(l) '**Village Development Officer**' means the person who are substantively appointed under the rules or orders in force before the commencement of these rules and further are going to be appointed under these rules;

(m) '**Year of recruitment**' means the period of 12 months beginning on the first day of July of any Calendar year.

PART-II- CADRE

4. (1) The strength of the service and of each Category of posts therein shall be as such as may be determined by the Government from time to time. Cadre of the Service

(2) The strength of the service and of each Category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below:-

Sl.No.	Name of Post	Number of Posts		Total Posts
		Permanent	Temporary	Total
1	Village Development Officer	8297	---	8297

Provided that -

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may, create such additional temporary or permanent posts as he may consider proper.

PART- III-RECRUITMENTSource of
recruitment

5. By direct recruitment through the Commission.

Reservation

6. Reservation for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the "Act" and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 and also in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART- IV- QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate For direct recruitment to a post in the service must be;

(a) a citizen of India, or

(b) a Tibetan refugee who came to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka or any East African country of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate in category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that the candidates belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and retention of such a candidate in beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note— A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained him or issued in his favour.

Academic
Qualifications

8. (1) A candidate For direct recruitment to the service must have passed the Intermediate Examination from the U.P.Board of High School and Intermediate Education or an examination Recognised by the Governor as equivalent there to.

(2) 'CCC' certificate in computer operation awarded by the NIELIT (formerly DOEACC Society).

Preferential
Qualifications

9. A candidate who has -

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a "B" certificate of the National Cadet Corps shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years of age and must not have attained the age of more than 40 years on the 1st day of July of calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as notified by the Government from time to time, shall be greater by such number of years as may be specified.

11. The character of the candidate for direct recruitment to any post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Character

Note— Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority, or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offense involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having wife living shall not be eligible for appointment to any post in the service:

Marital status

Provided that the Government may if satisfied that there exist special grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

13. No candidate will be appointed to any post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before any candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of Financial Handbook Volume II, Part III.

Physical
Fitness

PART- V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. The appointing authority will determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other categories under Rule 6 and will intimate the same to the Commissioner. The Commissioner shall compile the information received from the appointing authority and send a requisition for direct recruitment to the Commission.

Determination
of vacancies

15. Direct recruitment to the post of Village Development Officer in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group C posts (Mode and Procedure) Rules, 2015 as amended from time to time. The Commission will forward the list of selected candidates to the Commissioner, who will send the names to the appointing authorities for issuing appointment orders.

Procedure for
Direct
recruitment

PART- VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

16. After receiving the recommendation from the Commission, it will be examined by the Commissioner and will be sent to the concerned appointing authorities for appointment. The appointment order will be issued by the appointing authority after ensuring compliance with all service conditions.

Appointment

17. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant Probation Rules, 2013 as amended from time to time.

Probation

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

18. Subject to the provisions of sub-rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if -

Confirmation

- (a) he has passed the prescribed departmental examination, if any,
- (b) He has successfully undergone the prescribed training, if any,
- (c) his work and conduct is reported to be satisfactory,
- (d) his integrity is certified, and
- (e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority 19. The seniority of persons substantively appointed in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART- VII- PAY ETC.

Scales of pay 20. (1) The pay scale and allowances admissible to the persons substantively appointed to the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules is given below:-

Name of the Post	Pay Scale
Village Development Officer	Pay Matrix Level 3, 21700-69100

Pay during Probation 21. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection.

PART-VIII- OTHER PROVISIONS

Canvassing 22. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 23. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in conditions of service 24. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Repeal and Savings 25. The Uttar Pradesh Rural Development (Gram Sewak) Service Rules, 1980 is hereby repealed.

By order,
HIMANSHU KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv,
Uttar Pradesh Shasan.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 106 राजपत्र-2025-(296)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 ग्राम्य विकास-2025-(297)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।